पूर्व से कुल एक लाख मीटरी टन से बढ़ाकर जनवरी, 1969 में 1·26 लाख मीटरी टन और मई, 1969 से 1·59 लाख मीटरी टन कर दिया है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि इन कोटों को मुख्यत: घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण किया जाए। चीनी कारखानों को खुले बाजार में बिक्री के लिए दिया जाने वाला मासिक कोटा चरणों में गत वर्ष के 60,000 मीटरी टन से बढ़ाकर जनवरी, 1969 से 70,000 मीटरी टन और जून, 1969 से 95,000 मीटरी टन कर दिया गया है। थोक उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताएं खुले बाजार से चीनी खरीद कर पूर्ण करनी होती हैं। राज्यों में आवंटित कोटों के लिए वितरण की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Freight Costs of Fertilisers

1657. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that owing to the slowing down in the Vietnam war, the freight costs of fertilisers to be shipped from the U. S. A. to India is likely to increase substantially, because of the fact that the U.S. has of late begun insisting on shipping fertiiisers in American bottoms In terms of the decision that 50 per cent of all fertiliser exports financed out the US Aid Credit should be carried under US Flag ;

(b) if so, the likely extent of increase in the freight costs and total amount of extra expenditure in terms of foreign exchange to be incurred on that account during the ensuing year ; and

(c) the Government's reaction thereto and whether any approach has been made by Government to the U. S. Government seeking relief from this extra burden ; if so, the U. S. Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) to (c). Under the terms of aid received from U.S.A. for the purchase of fertilisers, atleast 50% of fertilisers procured have to be carried in U.S. flag vessels. When U S. flag vessels are not available, U.S. Government allow fixtures under Non-U.S. flag vessels in excess of 50% limit. Since January 1968 onwards, there has been greater availability of U.S. vessels due to (i) reduction in food exports from that country, (ii) revision of the ceiling rates by U.S. Maritime Administration and (iii) release of U.S. vessels from other commitments.

Whereas the freight paid for the period July, 1967 to June, 1968 for 6.44 lakh tonnes on U.S. vessels was 22.3 million dollars, the freight paid for the period July, 1968 to June, 1969 for carrying 6.96 lakh tonnes was 29.7 million dollars. In the circumstances stated above, there is no question of U.S.A. insisting on this country carrying 50% of fertilisers by U.S. flag vessels or Government of India seeking relief from the U.S. Government.

Sugar Prices

1658. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the reasons for keeping two prices of sugar (controlled and free market) in the country ; and

(b) whather it is a fact that the repercussions of such policy will be hard hitting to farmers in the long run who apprehend low gur prices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The policy of partial decontrol of sugar under which part of the production is procured by Government at fixed prices, and the the rest is released to the sugar factories for sale at open market prices was adopted with a view to :—

(i) facilitate payment of a higher

sugarcane price by sugar factories to the sugarcane growers ;

(ii) arrest the tendency of fall in area under sugarcane during two successive years 1966-67 and 1967-68, by incentive to cane growers through (i) above ;

(iii) maximise production of sugar ; and

(iv) make available sugar to domestic consumers and for Defence Services, exports etc. at a cheaper price.

(b) No, Sir.

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के गोदाम

1659. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थित केन्द्रीय सरकार के गोदामों और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भण्डागारों पर इस समय कुल कितनी राशि खर्च की जाती है ;

(ख) इन गोदामों अथवा भाण्डागारों से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है ;

(ग) इस समय इन गोदामों में कुल कितना स्टाक है ; और

(घ) उनके रख-रखाव तथा कर्मचारियों पर प्रति मास कितनी राशि खर्च की जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य विभाग के खाद्यान्नों के सभी गोदाम भारतीय खाद्य निगम को हस्तान्तरित कर दिये गए हैं। केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने इन्दौर, भाटापाड़ा तथा मुरैना, में भाण्डागार। गोदाम बनाने हेतु 31 मार्च, 1969 तक 23,79,520 रुपये खर्च किये थे। इन्दौर में निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है।

(ख) से (घ). इन्दौर, भाटापाड़ा, मुरैना में स्थित तीन भाण्डागार। गोदामों के बारे में सूचना इस प्रकार है :

	इन्दौर	भाटापाड़ा	मुरैना
(1) भाण्डागारों और रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी	6 किलोमीटर	$2\frac{1}{2}$ किलोमीटर	2 किलोमीटर
(2) 30 जून, 1969 के कुल स्टाक	4,987 मी० ट०	4,259 मी०ट०	5,870 मी०ट०
(3) 1968-69 के दौरान इन पर औसत मासिक खर्च			
रख रखाव :	कुछ नहीं †	512.33 रु०	904·16 रु०
स्टाफ :	2,972·95 रु०	1,703·25 रु०	1,948·15 रु०

†—ये गोदाम हाल ही में पूरे किये गए थे।

लघु सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश को सहायता

1660. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सिंचाई परियोजनाओं, भू-विकास तथा कृषि उत्पादन के लिए 1967-68 और 1968-69 में मध्य प्रदेश सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त प्रयोजनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में कितनी सहायता माँगी थी ; और

(ग) 1969-70 के लिए मांगी गई राशि